Housing/Workshed Scheme for Handloom Weavers

3475. SHRI SURINDER KUMAR SINGLA:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the number of worksheds and houses built till now under the Workshed-cum-Housing Scheme for the Handloom weaver;

(b) the number of handloom weavers who have taken benefit of this scheme; and

(c) the other steps being taken in this area?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a)

No. of Workshed-cum-House built.	No. of workshed built.
50,418	1,20,479

(b) 1,70,897 weavers.

(c) Keeping in view importance of the scheme, enhanced allocation has been kept in the current year.

Proper Training of Dyeing and Printing to Handloom Weavers

3476. SHRI JAGIR SINGH DARD:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether the National Handloom Development Corporation has given proper training of dyeing and printing to the beneficiaries;

(b) if so, the details of Maharashtra and Punjab;

(c) the response to this scheme; and

(d) the other steps being taken by the Corporation for the sake of handloom weavers?

THE MINISTER FOR TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) Yes Sir.

(b) The details of the Programmes organised in the States of Maharashtra & Punjab are as under:—

	(A) LAB TRAINING		(B) ECO-FRIENDLY	
	No. of Programme/baches	No. of beneficiaries	No. of Programme/baches.	No. of beneficiaries.
Maharashtra	18	98	5	165
Punjab	7	19	1	24

(c) The National Handloom Development Corporation is receiving over whelming response from various State Handloom Directorates. Request have been received to organise the Eco-friendly Training Programme in Handloom Cluster areas is other States also.

(d) The other steps being taken by the Corporation are as under:—

(A) Raw Materials Supplies.
1. Yarn Supplies.
2. Dyes & Chemicals supplies.

(B) Orientation Programme for Quality Dyeing Units.

(C) Product Awareness and Transfer of Eco-Friendly Dyestuff know how.

(D) Silk Printing Workshop—4 Days duration.

(E) Organising Appropriate Technology Exhibitions.

(F) Programme on Propogation of Jute Yarn.

(G) Natural Dyes Promotion.

(H) Marketing of Handloom Products.

(I) Organisation of Seminars/ Workshop/Courses on Human Resource Development in Handloom Sector.

रेशम उद्योग के विकास के लिए परियोजनाएं

3477. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्णाटक, पूर्वोत्तर क्षेत्र और मध्य-प्रदेश में रेशम उद्योग के विकास के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वहां इस उद्योग के विकास के लिए योजना-व्यय और गैर-योजना व्यय के लिए आवंटित राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य और अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियां क्या-क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर० एल० जालप्पा): (क) राज्यों में रेशम उद्योग का विकास करने के कार्यक्रमों/परियोजनाओं को मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शुरू किया जाता है। तथापि, राज्यों के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड राज्यों के सहयोग से रेशम उत्पादन विकास की (शहतूती तथा गैर-शहतूती दोनों प्रकार की) परियोजनाएं शुरू करता है। प्रमुख परियोजनाओं जिनसे विशेषकर पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेशम उत्पादन का विस्तार हुआ है। वे हैं:— कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के चुनिंदा जिलों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक रूप से विकसित किए जाने वाले तसर कोसों के विकास की परियोजना तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्य योजना।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक, पूर्वोत्तर राज्यों तथा मध्य प्रदेश में अपने राज्य विशिष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एककों (योजना और गैर योजना) दोनों के अंतर्गत पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किए गए कुल व्यय के ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(करोड़ रु० में)

	कर्नाटक	पूर्वोत्तर	मध्य प्रदेश
1992-93	7.27	2.32	1.04
1993-94	8.38	3.90	1.25
1994-95	12.93	4.53	1.32
1995-96	6.16	5.99	5.16
1996-97*	2.34	1.80	0.96

(*सितंबर, 96 तक)

(ग) कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के चुनिंदा जिलों में तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम में क्रियान्वित राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अंतर्गत पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी सहायता के सृजन के अतिरिक्त उपलब्ध प्राक्कलनों के अनुसार शहतूती कृषि के अंतर्गत क्रमशः 127437 एकड़, 1145.50 एकड़ तथा 991 एकड़ क्षेत्र लाया गया है। आठवीं योजनावधि के दौरान (सितंबर, 96 तक) मध्य प्रदेश में प्राकृतिक रूप से विकसित किए जाने वाले तसर कोसों का विकास करने की परियोजना के अंतर्गत 125.38 लाख कोसों की कुल मात्रा रिलीज की गयी। इसी प्रकार पूर्वोत्तर राज्यों में रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए कार्य योजना के अंतर्गत कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन किया गया तथा साथ ही शहतूती रोपण के लिए 7500 एकड़ के परियोजना के लक्ष्य की तुलना में 2479 क्षेत्र में शहतूती रोपण (दिसंबर, 1996 तक) का कार्य किया गया।